>

Title : Need to provide irrigation facilities in tribal areas of the country on priority basis.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): माननीय सभापति महोदय, आज देश को आज़ाद हुए 64 साल हुए हैं, किन्तु देश के गरीब, आदिवासी लोग जो खासकर जंगलों में, पहाड़ों में खेती-बाड़ी करके अपना लालन-पालन कर रहे हैं, उनके खेतों को सिंचाई की सुविधा से अभी तक वंचित किया हुआ है। खेती-बाड़ी के लिए पानी का होना अत्यावश्यक है। आदिवासी लोग अपने खेतों को पानी देने के लिए पूरी तरह से बरसात पर निर्भर हैं। आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र पंद्रह प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र है। केन्द्र सरकार ने आज तक उनको सिंचाई की सुविधा दिए जाने हेतु कोई विधान नहीं बनाया है। देश में कितने आदिवासी लोग हैं और उनकी कितनी भूमि सिंचित है, ऐसे कोई आंकड़ें सरकार के पास नहीं है। इन सब उपेक्षाओं के कारण उनका जीवन-स्तर अन्य वर्गों की अपेक्षा कमज़ोर है। सरकार कहती है कि 99 बड़ी एवं 140 मध्यम सिंचाई योजना जनजातीय क्षेत्रों में बनाई है। इस तरह से सरकार आदिवासी लोगों को गुमराह कर रही है। आदिवासी लोग मेहनती हैं। उनकी ज़मीन भी उबड़-खाबड़ है, परन्तु उपजाऊ है। मगर, सिंचाई के अभाव में वे अपने खेतों में अच्छी फसल खड़ी करने में असमर्थ हैं। सरकार कहती है कि उन्होंने त्वरित सिंचाई लाभार्थी योजना चला रखी है, परन्तु इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। जनजाति विकास के लिए अलग से मंत्रालय है, परन्तु इस मंत्रालय ने सिंचाई के लिए अपना कोई योगदान नहीं दिया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के नर्मदा जिला और भरूच जिले के सागपाड़ा, डेडियापाड़ा और वालिया तालुका आदिवासी क्षेत्रों में पूरी तरह से आता है और चारों तालुकाओं में सिंचाई की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि देश के आदिवासियों को अन्य समुदायों के साथ जोड़ना है तो उनको भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।[MSOffice12]